

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1815

10/02/2026 को उत्तरार्थ

विषय: स्मार्ट कृषि-खाद्य प्रणालियां और सतत उत्पादन पद्धतियां

1815. श्रीमती भारती पारधी:

श्री नरेश गणपत म्हस्के:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री श्रीरंग आप्पा चंद्र बारणे:

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जलवायु-अनुकूल, कार्बन-तटस्थ और पुनर्योजी कृषि जैसी प्रमुख कृषि प्राथमिकताओं की पहचान की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) स्मार्ट कृषि-खाद्य प्रणालियों के प्रमुख घटक क्या हैं और उनमें शामिल सतत उत्पादन पद्धतियां कौन सी हैं;

(ग) क्या सरकार का इन कृषि प्राथमिकताओं के साथ एनएमएसए, पीएमकेएसवाई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, डिजिटल कृषि मिशन और प्राकृतिक खेती जैसी मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करने का विचार है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) चिन्हित किए गए मुद्दों के आधार पर वैज्ञानिकों, छात्रों और किसानों के अनुसंधान, नवाचार और क्षमता संवर्धन को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या इन कृषि संबंधी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से भविष्य की कृषि नीति-निर्माण निर्देशित होने की संभावना है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख) सरकार ने जलवायु परिवर्तन, संसाधन क्षरण और सतत खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए जलवायु-अनुकूल, कार्बन-अनुकूल और पुनर्योजी कृषि सहित प्रमुख कृषि संबंधी प्राथमिकताओं की पहचान की है। सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत कई योजनाएं शुरू की गई हैं। 'प्रति बूंद अधिक फसल' योजना सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों, जैसे ड्रिप सिंचाई और स्प्रींकलर सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाती है। वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास योजना उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली पर केंद्रित है। मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देती है। बागवानी, कृषि वानिकी के समेकित विकास मिशन और राष्ट्रीय बांस मिशन भी जलवायु लचीलेपन को बढ़ावा देते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के साथ मिलकर, प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को फसल खराब होने के खिलाफ व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) जलवायु परिवर्तन से प्रभावित कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआर) नामक परियोजना चला रही है, जो कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करती है और जलवायु परिवर्तन के कारण जिला स्तर पर जोखिम और संवेदनशीलता का आकलन करती है। एनआईसीआर के अंतर्गत, 310 जिलों को जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से संवेदनशील घोषित किया गया है, जिनमें से 109 जिलों को 'अत्यधिक संवेदनशील' और 201 जिलों को 'अत्यधिक संवेदनशील' श्रेणी में रखा गया है। किसानों की अनुकूलन क्षमता और लचीलापन बढ़ाने के लिए, इस परियोजना के तहत 151 जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से 448 जलवायु परिवर्तन से प्रभावित गांवों में स्थान-विशिष्ट जलवायु परिवर्तन से प्रभावित प्रौद्योगिकियों (जैसे धान सघनता प्रणाली, वायुजनित धान, धान की सीधी बुवाई, शून्य जुताई वाली गेहूं की बुवाई आदि) का प्रदर्शन किया गया है। बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एनआईसीआर के अंतर्गत ग्राम स्तरीय बीज बैंकों और सामुदायिक नर्सरियों के लिए क्षमता निर्माण कार्य किया जाता है। एनआईसीआर के कई गांवों में सूखे और बाढ़ सहिष्णु तथा जलवायु-प्रतिरोधी धान, गेहूं, सोयाबीन, सरसों, चना, ज्वार, ग्राम और बाजरा की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। इसके अतिरिक्त, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) के अंतर्गत कृषि पद्धतियों से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आईसीएआर ने पिछले 10 वर्षों (2014-2024) के दौरान 2900 किस्में जारी की हैं, जिनमें से 2661 किस्में एक या अधिक जैविक और/या अजैविक तनावों के प्रति सहिष्णु हैं।

(ग) सरकार डिजिटल रूपांतरण, मृदा स्वास्थ्य, जल उपयोग दक्षता, जैविक/प्राकृतिक खेती और अन्य सतत कृषि पद्धतियों सहित व्यापक कृषि प्राथमिकताओं के साथ मौजूदा कृषि योजनाओं को धीरे-धीरे संरक्षित और एकीकृत कर रही है। इस प्रकार के एकीकरण से अधिक एकीकृत और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा, अभिसरण में सुधार होगा, प्रयासों की पुनरावृत्ति कम होगी, संसाधनों का अधिकतम उपयोग होगा और कार्यान्वयन दक्षता मजबूत होगी।

(घ) और (ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, प्रदर्शन और क्षमता विकास के जनादेश के साथ 731 कृषि केंद्र स्थापित किए हैं। ये केंद्र किसानों के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की नई प्रौद्योगिकियों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिनमें जलवायु-लचीली और पुनर्योजी कृषि से संबंधित प्रौद्योगिकियां भी शामिल हैं। सरकार कृषि नीतियों को जलवायु-लचीली कृषि, टिकाऊ और पुनर्योजी कृषि पद्धतियों, मृदा और जल संरक्षण, संसाधन उपयोग दक्षता, फसल प्रणालियों के विविधीकरण और पर्यावरणीय पदचिह्न में कमी जैसी पहचानी गई कृषि प्राथमिकताओं के साथ संरक्षित कर रही है।
